

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 628वीं बैठक दिनांक 13/03/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

**1. Case No 9311/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 15.850 ha. (28,530 cum per annum) (Khasra No. 247, 290) Village - Dhaur-3, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 247, 290) Village - Dhaur-3, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind (M.P.) 15.85 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 596वीं दिनांक 23/09/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के विवरण में पेज नं.—102 के सरल क्रमांक—22 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)— 39,000 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 28,530 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत) से कम है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा सड़क पर जल छिड़काव हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप हैं उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 28,530 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 13.26 लाख लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 12.56 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 11.98 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयं वृक्षों की प्रजातियों चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

| क्र.            | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान                                                    | पौधों की प्रजातियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मात्रा<br>(संख्या में) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Up to June 2023 | In 1 to 6th row along the river bank                                                     | From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing ( Between land and bank) and Other Local species<br>From 4th to 5 <sup>th</sup> row : Katang bans.<br>In 6 <sup>th</sup> Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing trees local species etc. | 2000<br>1000<br>150    |
| Up to June 2023 | For Village distribution specially to the farmers whose land are near to the river bank. | Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.                                                                                                                                                                                                                                                       | 11700                  |
| Up to June 2023 | Evacuation route                                                                         | Aam, Chiroli, Neem, Jangal Jalebi, Kadam and other local species.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000                   |
|                 | <b>योग</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15850                  |

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 07.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून, 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

| सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि                                                                                                                                      | राशि (रु. में) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| One kitchen room with platform, 2 Toilet at Govt. primary School, Village Dhore with facility of water through bore well at School. 5KW solar panel with power back-up | 6.00           |
| Health equipments to the nearest PHC Village Dhaura                                                                                                                    | 1.00           |

2. **Case No 9317/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 19.0 ha. (1,14,000 cum per annum) (Khasra No. 546, 850) Village - Khairoli, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 546, 850) Village - Khairoli, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind (M.P.) 19.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 596वीं दिनांक 23/09/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि टॉर की शर्त अनुसार इस खदान की डी.जी.पी.एस. कॉआर्डिनेट कराये गये थे जो अभी संबंधित खनन अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किये गये हैं अतः समिति ने डी.एस.आर. कॉआर्डिनेट के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के कुछ भाग में पानी भरा हुआ है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अपलोडेड गूगल इमेज पुरानी (दिसम्बर, 2022) है जिस कारण आवंटित खनन क्षेत्र में पानी दिख रहा है किंतु जनवरी-फरवरी के पश्चात् पानी उतर जाता है तथा आवंटित खनन क्षेत्र से रेत निकाली जा सकती है तथा इसी के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सर्वे कर जिला समिति द्वारा उसको तैयार किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा क्योंकि कुल आवंटित क्षेत्र 19.00 हे. में से मात्र 10.38 हे. में ही खनन कार्य प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मार्गदर्शिका, 2020 के अनुसार कुल आवंटित क्षेत्र के 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही खनन किया जाना है)। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के विवरण में पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-24 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-1,26,500 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 1,14,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत) से कम है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के दक्षिणी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई है तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 1,14,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.83 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 30.19 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 13.55 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयनित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

| क्र. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान                                                   | पौधों की प्रजातियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मात्रा (संख्या में)     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | In 1 to 6th row along the river bank                                                    | From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing ( Between land and bank) and Other Local species<br>From 4th to 5 <sup>th</sup> row : Katang bans.<br>In 6 <sup>th</sup> Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc. | 2000<br><br>1000<br>300 |
| 2    | For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank. | Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.                                                                                                                                                                                                                                                       | 15600                   |

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

|   |                  |                                                                     |       |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 3 | Evacuation route | Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species. | 100   |
|   |                  | योग                                                                 | 19000 |

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 07.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून,2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

| सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि                                                                                                                                        | राशि (रु. में) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| One kitchen room with platform, 2 Toilet at Govt. primary School, Village Kharoli with facility of water through bore well at School. 5KW solar panel with power back-up | 6.00           |
| Health equipments to the nearest PHC Village Kharoli                                                                                                                     | 1.00           |

**3. Case No 9307/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 11.680 ha. (21,024 cum per annum) (Khasra No. 245, 246, 251) Village - Dhaur-2, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 245, 246, 251) Village - Dhaur-2, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind (M.P.) 11.680 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 596वीं दिनांक 23/09/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के उत्तर-पूर्व दिशा में 1350 मीटर पर एक ब्रिज है तथा नदी का कुछ भाग पानी में डूबा है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अपलोडेड गूगल इमेज पुरानी ( दिसम्बर, 2022) है जिस कारण आवंटित खनन क्षेत्र में पानी दिख रहा है किंतु जनवरी-फरवरी के

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

पश्चात् पानी उतर जाता है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र से रेत निकाली जा सकती है तथा इसी के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सर्वे कर जिला समिति द्वारा उसको तैयार किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वहाँ पर खनन् नहीं किया जायेगा क्योंकि कुल आवंटित क्षेत्र 11.680 हे. में से मात्र 06.22 हे. में ही खनन् कार्य प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मार्गदर्शिका, 2020 के अनुसार कुल आवंटित क्षेत्र के 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही खनन् किया जाना है)। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के विवरण में पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-21 पर माईनेवल मिनरल पोटेंशियल (60 प्रतिशत)-33,024 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 21,024 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोटेंशियल (60 प्रतिशत) से कम है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है । समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, वृक्षारोपण, पानी का छिड़काव, सामाजिक विकास के कार्य इत्यादि हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया । खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 21,024 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.17 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 12.56 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 09.89 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान                                                   | पौधों की प्रजातियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मात्रा (संख्या में)     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | In 1 to 6th row along the river bank                                                    | From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing ( Between land and bank) and Other Local species<br>From 4th to 5 <sup>th</sup> row : Katang bans.<br>In 6 <sup>th</sup> Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc. | 2000<br><br>1000<br>180 |
| 2   | For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank. | Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.                                                                                                                                                                                                                                                       | 8000                    |
| 3   | Evacuation route                                                                        | Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.                                                                                                                                                                                                                                                               | 500                     |
|     | योग                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11680                   |

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 07.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून,2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

| सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि                                                                                                                                                       | राशि (रु. में) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| One kitchen room with platform (8feet x 10feet), 2 Toilet at Govt. primary School, Village Dhaur with facility of water through bore well at School. 5KW solar panel with power back-up | 6.00           |
| Health equipments to the nearest PHC Village Dhaur                                                                                                                                      | 1.00           |

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

**4. Case No 9316/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 10.0 ha. (60,000 cum per annum) (Khasra No. 1420) Village - Goram 1420, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1420) Village - Goram, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind (M.P.) 10.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 596वीं दिनांक 23/09/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान में आंशिक रूप से पानी भरा हुआ है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अपलोडेड गूगल इमेज पुरानी (दिसम्बर, 2022) है जिस कारण आवंटित खनन क्षेत्र में पानी दिख रहा है किंतु जनवरी-फरवरी के पश्चात् पानी उतर जाता है तथा आवंटित खनन क्षेत्र से रेत निकाली जा सकती है तथा इसी के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सर्वे कर जिला समिति द्वारा उसको तैयार किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा क्योंकि कुल आवंटित क्षेत्र 10.00 हे. में से मात्र 06.00 हे. में ही खनन कार्य प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मार्गदर्शिका, 2020 के अनुसार कुल आवंटित क्षेत्र के 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही खनन किया जाना है)। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के विवरण में पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-23 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-71,000 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 60,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरान्त यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, वृक्षारोपण, पानी का छिड़काव, सामाजिक विकास के कार्य इत्यादि हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सके जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 60,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.33 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 09.43 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 09.05 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

| क्रं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियाँ                                                                                                                                                     | मात्रा<br>(संख्या में) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | In 1 to 6th row along the river bank  | From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing ( Between land and bank) and Other Local | 2000                   |

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

|   |                                                                                         |                                                                                                                                                           |             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   |                                                                                         | species<br>From 4th to 5 <sup>th</sup> row : Katang bans.<br>In 6 <sup>th</sup> Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc. | 1000<br>100 |
| 2 | For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank. | Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.                                                                               | 6400        |
| 3 | Evacuation route                                                                        | Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.                                                                                       | 500         |
|   | योग                                                                                     |                                                                                                                                                           | 10,000      |

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 07.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून,2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

| सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि                                                                                                                                      | राशि (रु. में) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| One kitchen room with platform, 2 Toilet at Govt. primary School, Village Goram with facility of water through bore well at School. 5KW solar panel with power back-up | 6.00           |
| Health equipments to the nearest PHC Village Goram                                                                                                                     | 1.00           |

**5. Case No 9306/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 14.710 ha. (44010 cum per annum) (Khasra No. 66, 75) Village - Matiyawali-1, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 66, 75) Village - Matiyawali -1, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind, (M.P.) 14.710 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 596वीं दिनांक 23/09/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस,

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि टॉर की शर्त अनुसार इस खदान की डी.जी.पी.एस. कॉआर्डिनेट कराये गये थे जो अभी संबंधित खनन अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किये गये हैं अतः समिति ने डी.एस.आर. कॉआर्डिनेट के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान में आंशिक रूप से पानी भरा हुआ है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अपलोडेड गूगल इमेज पुरानी (दिसम्बर, 2022) है जिस कारण आवंटित खनन क्षेत्र में पानी दिख रहा है किंतु जनवरी-फरवरी के पश्चात् पानी उतर जाता है तथा आवंटित खनन क्षेत्र से रेत निकाली जा सकती है तथा इसी के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सर्वे कर जिला समिति द्वारा उसको तैयार किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा क्योंकि कुल आवंटित क्षेत्र 14.710 हे. में से मात्र 07.116 हे. में ही खनन कार्य प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मार्गदर्शिका, 2020 के अनुसार कुल आवंटित क्षेत्र के 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही खनन किया जाना है)। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के विवरण में पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-27 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-55,010 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 44,010 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, वृक्षारोपण, पानी का छिड़काव, सामाजिक विकास के कार्य इत्यादि हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप हैं उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 44,010 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.68 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 13.18 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 11.40 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

| क्र. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान                                                   | पौधों की प्रजातियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मात्रा (संख्या में)     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | In 1 to 6th row along the river bank                                                    | From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing ( Between land and bank) and Other Local species<br>From 4th to 5 <sup>th</sup> row : Katang bans.<br>In 6 <sup>th</sup> Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc. | 2000<br><br>1000<br>100 |
| 2    | For Village distribution specially to the famers who's land are near to the river bank. | Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.                                                                                                                                                                                                                                                       | 11000                   |
| 3    | Evacuation route                                                                        | Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.                                                                                                                                                                                                                                                               | 600                     |
|      | योग                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,700                  |

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 08.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून, 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

| सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि                                                  | राशि (रु. में) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Maintenance of village road (1km@2.00laks per km)                                  | 2.00           |
| Cleaning, plantation (100no.) and whitewash of Matiyawali school                   | 3.00           |
| Cleaning, whitewash and Plantation at Temple 100no. with regular water arrangement | 3.00           |

**6. Case No 9310/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 9.0 ha. (54,000 cum per annum) (Khasra No. 1576) Village - Ajnar-2, Tehsil - Lahar, Dist. Bhind, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1576) Village - Ajnar-2, Tehsil - Lahar, Dist. Bhind (M.P.) 9.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 596वीं दिनांक 23/09/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान का कुछ भाग पानी में डूबा है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अपलोडेड गूगल इमेज पुरानी (नवम्बर, 2021) है जिस कारण आवंटित खनन क्षेत्र में पानी दिख रहा है किंतु जनवरी-फरवरी के पश्चात् पानी उतर जाता है तथा आवंटित खनन क्षेत्र से रेत निकाली जा सकती है तथा इसी के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सर्वे कर जिला समिति द्वारा उसको तैयार किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा क्योंकि कुल आवंटित क्षेत्र 09.00 हे. में से मात्र 04.56 हे. में ही खनन कार्य प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मार्गदर्शिका, 2020 के अनुसार कुल आवंटित क्षेत्र के 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही खनन किया जाना है)। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के विवरण में

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-15 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-65,200 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 54,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है । समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, वृक्षारोपण, पानी का छिड़काव, सामाजिक विकास के कार्य, मशीन से खनन नहीं, आवंटित स्थल में रेत नहीं इत्यादि हेतु सुझाव/आपत्ति प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानो/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 54,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 09.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 11.12 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 08.55 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयं वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:—

| क्र. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान                                                   | पौधों की प्रजातियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मात्रा<br>(संख्या में)  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | In 1 to 6th row along the river bank                                                    | From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing ( Between land and bank) and Other Local species<br>From 4th to 5 <sup>th</sup> row : Katang bans.<br>In 6 <sup>th</sup> Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc. | 2000<br><br>1000<br>100 |
| 2    | For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank. | Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.                                                                                                                                                                                                                                                       | 5000                    |
| 3    | Evacuation route                                                                        | Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.                                                                                                                                                                                                                                                               | 900                     |
|      | योग                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9000                    |

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 07.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून,2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :—

| सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि                           | राशि (रु. में) |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Maintenance of village road (1km@2.00laks per km            | 2.00           |
| Cleaning, plantation (100no.) and whitewash of Ajnar school | 3.00           |
| Plantation at Temple 100no. with regular water arrangement  | 2.00           |

7. **Case No 9313/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 18.230 ha. (32,814 cum per annum) (Khasra No. 1, 2, 12, 45, 67) Village - Dhaur-1, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1, 2, 12, 45, 67) Village - Dhaur-1, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind (M.P.) 18.230 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 596वीं दिनांक 23/09/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 750 मीटर पर एक ब्रिज है तथा आवंटित खनन क्षेत्र ब्रिज के अपस्ट्रीम में है तथा खदान का कुछ भाग पानी में डूबा है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अपलोडेड गूगल इमेज पुरानी (दिसम्बर, 2022) है जिस कारण आवंटित खनन क्षेत्र में पानी दिख रहा है किंतु जनवरी-फरवरी के पश्चात् पानी उतर जाता है तथा आवंटित खनन क्षेत्र से रेत निकाली जा सकती है तथा इसी के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सर्वे कर जिला समिति द्वारा उसको तैयार किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा क्योंकि कुल आवंटित क्षेत्र 18.230 हे. में से मात्र 09.84 हे. में ही खनन कार्य प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मार्गदर्शिका, 2020 के अनुसार कुल आवंटित क्षेत्र के 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही खनन किया जाना है)। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के विवरण में पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-20 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-42,814 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 32,814 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, वृक्षारोपण, पानी का छिड़काव, सामाजिक विकास के कार्य इत्यादि हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारो पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारो के कटाव को रोका जा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 32,814 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 15.15 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 12.71 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 13.87 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

| क्र. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मात्रा (संख्या में)         |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1    | In 1 to 6th row along the river bank  | From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing ( Between land and bank) and Other Local species<br>From 4th to 5 <sup>th</sup> row : Katang bans.<br>In 6 <sup>th</sup> Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc. | 2000<br><br>1000<br><br>230 |

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

|   |                                                                                         |                                                                             |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2 | For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank. | Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species. | 17000 |
| 3 | Evacuation route                                                                        | Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.         | 1000  |
|   | योग                                                                                     |                                                                             | 18230 |

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 03.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून,2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

| सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि                               | राशि (रु. में) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Cleaning/Maintenance of Dhaur school and plantation near Mandir | 2.00           |
| Health equipments to the nearest PHC Village Dhaur              | 1.00           |

**8. Case No 9315/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 11.170 ha. (1,02,000 cum per annum) (Khasra No. 1713, 2278, 2435) Village - Bharaulikala, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind, MP M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1713, 2278, 2435) Village - Bharaulikala, Tehsil - Mehgaon, Dist. Bhind (M.P.) 11.170 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 596वीं दिनांक 23/09/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

अनुसार अनुसार खदान के कुछ भाग में पानी भरा हुआ है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अपलोडिड गूगल इमेज पुरानी ( दिसम्बर, 2022) है जिस कारण आवंटित खनन् क्षेत्र में पानी दिख रहा है किंतु जनवरी-फरवरी के पश्चात् पानी उतर जाता है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र से रेत निकाली जा सकती है तथा इसी के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सर्वे कर जिला समिति द्वारा उसको तैयार किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वहाँ पर खनन् नहीं किया जायेगा क्योंकि कुल आवंटित क्षेत्र 11.170 हे. में से मात्र 06.552 हे. में ही खनन् कार्य प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मार्गदर्शिका, 2020 के अनुसार कुल आवंटित क्षेत्र के 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही खनन् किया जाना है)। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के विवरण में पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-19 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-1,22,000 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 1,02,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिणी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है । समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, वृक्षारोपण, पानी का छिड़काव, सामाजिक विकास के कार्य के अंतर्गत आगानबाडी से सिंधु नदी तक डामरीकरण इत्यादि हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 1,02,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.92 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 18.98 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 09.64 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:—

| क्र. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान                                                   | पौधों की प्रजातियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मात्रा (संख्या में)     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | In 1 to 6th row along the river bank                                                    | From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing ( Between land and bank) and Other Local species<br>From 4th to 5 <sup>th</sup> row : Katang bans.<br>In 6 <sup>th</sup> Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc. | 2000<br><br>1000<br>170 |
| 2    | For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank. | Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.                                                                                                                                                                                                                                                       | 9700                    |
| 3    | Evacuation route                                                                        | Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1300                    |
|      |                                                                                         | <b>योग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11170</b>            |

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 07.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून,2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :—

| सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि                                                                                                                                              | राशि (रु. में) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| One kitchen room with platform, 2 Toilet at Govt. primary School, Village BharauliKalan with facility of water through bore well at School. 5KW solar panel with power back-up | 6.00           |
| Health equipments to the nearest PHC Village BharauliKalan                                                                                                                     | 1.00           |

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

**9. Case No 9309/2022 Shri Raghvendra Singh, C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Dist. Jaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 24.90 ha. (36,924 cum per annum) (Khasra No. 1) Village - Badettar, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1) Village - Badettar, Tehsil - Mihona, Dist. Bhind (M.P.) 24.90 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 596वीं दिनांक 23/09/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के दक्षिण दिशा में 1345 मीटर पर एक ब्रिज है तथा खदान का कुछ भाग पानी में डूबा है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अपलोडेड गूगल इमेज पुरानी (दिसम्बर, 2022) है जिस कारण आवंटित खनन क्षेत्र में पानी दिख रहा है किंतु जनवरी-फरवरी के पश्चात् पानी उतर जाता है तथा आवंटित खनन क्षेत्र से रेत निकाली जा सकती है तथा इसी के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सर्वे कर जिला समिति द्वारा उसको तैयार किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा क्योंकि कुल आवंटित क्षेत्र 24.90 हे. में से मात्र 11.61 हे. में ही खनन कार्य प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मार्गदर्शिका, 2020 के अनुसार कुल आवंटित क्षेत्र के 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही खनन किया जाना है)। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के विवरण में पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-16 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) 46,924 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 36,924 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के दक्षिणी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है । समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, वृक्षारोपण, पानी का छिड़काव, सामाजिक विकास के कार्य के अंतर्गत डामरीकरण, अस्पताल, गौशाला इत्यादि हेतु सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम. पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 36,924 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.83 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 12.52 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 16.55 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयं वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियाँ | मात्रा<br>(संख्या में) |
|-----|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
|-----|---------------------------------------|---------------------|------------------------|

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

|   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | In 1 to 6th row along the river bank                                                    | From 1st to 3rd Row over the land located near to agricultural land : Khas and Leman Grass, Slips of Agav, Gatayan Seed sowing ( Between land and bank) and Other Local species<br>From 4th to 5 <sup>th</sup> row : Katang bans.<br>In 6 <sup>th</sup> Row : Karanj, Jamun, Lasoda, other fruit bearing tress local species etc. | 2000<br><br>1000<br>400 |
| 2 | For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank. | Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,100                  |
| 3 | Evacuation route                                                                        | Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1500                    |
|   | योग                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25000                   |

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 10.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून,2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

| सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि                              | राशि (रु. में) |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Maintenance of village road (1km@2.00laks per km               | 2.00           |
| Cleaning, plantation (100no.) and whitewash of Badettar school | 3.00           |
| Plantation at Temple 100no. with regular water arrangement     | 2.00           |
| Construction of teen shed for Goushala                         | 3.00           |

**10. Case No 9746/2023 Shri Raghvendra Singh, R/o C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, District-Jaipur (RJ)-302021, Prior Environment Clearance for Sadha River Sand Mining Project in an area of 5.00 ha. (25080 Cum per annum) (Khasra No. 801), Village-Sadha, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP)**

This is case of Sand Mining. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 801), Village-Sadha, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP) 5.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इन्वायरो

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरुग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6233 दिनांक 20/10/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है एवं इनका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। बैठक के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान का 50 प्रतिशत भाग पानी में डूबा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नदी का वह भाग जो पानी में डूबा होगा वहाँ पर खनन प्रस्तावित नहीं किया जायेगा तथा ई.आई.ए. के साथ पुनरीक्षित उत्पादन योजना प्रस्तुत की जायेगी। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-103 के सरल क्रमांक-34 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-30,000 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 25,080 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत) से कम है। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके तथा इसी के अनुरूप वृक्षारोपण योजना में प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। इसी प्रकार समिति ने सुझाव दिया कि भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थरीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

2. खदान का 50 प्रतिशत भाग पानी में डूबा है एवं नदी का वह भाग जो पानी में डूबा होगा वहाँ पर खनन प्रस्तावित नहीं है अतः ई.आई.ए. के साथ पुनरीक्षित उत्पादन योजना प्रस्तुत की जाये।
3. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थरीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
9. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
10. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
11. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।
12. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
13. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
14. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

15. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
16. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

**11. Case No 9747/2023 Shri Raghvendra Singh, R/o C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, District-Jaipur (RJ)-302021, Prior Environment Clearance for Barethi Khurd River Sand Mine in an area of 4.00 ha. (43200 Cum per annum) (Khasra No. 434), Village-Barethi Khurd, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP)**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 434), Village-Barethi Khurd, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5551 दिनांक 12/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है जिनका का क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।

यह रेत सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर खदान में से नदी की धारा निकल रही है, अतः नदी की धारा को छोड़ते हुए पुनरीक्षित उत्पादन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये । परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-18 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-53,500 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 43,200 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत) से कम है । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके ।

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके तथा इसी के अनुरूप वृक्षारोपण योजना में प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। इसी प्रकार समिति ने सुझाव दिया कि भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थरीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. खदान में से नदी की धारा निकल रही है, अतः नदी की धारा को छोड़ते हुए पुनरीक्षित उत्पादन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थरीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

9. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
12. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
14. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।
15. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
16. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

**12. Case No 9748/2023 Shri Raghvendra Singh, R/o C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, District-Jaipur (RJ)-302021, Prior Environment Clearance for Barethi Khurd 01 River Sand Mining Project in an area of 13.00 ha. (52500 Cum per annum) (Khasra No. 284, 515), Village-Barethikhurd, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP)**

This is case of Sand Mining. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 284, 515), Village-Barethikhurd, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP) 13.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इवायरो इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरुग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6229 दिनांक 20/10/22 अनुसार

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है एवं इनका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के एक भाग से नदी की धारा निकल रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में नदी की धारा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा तथा पुनरीक्षित उत्पादन योजना ईआईए के साथ प्रस्तुत की जायेगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि इसी खदान के दूसरी ओर एक अन्य खदान (प्रकरण क्रमांक 9750/23) आवंटित की गई है जिसमें से नदी की धारा बह रही है। नदी की धारा अवरुद्ध न हो तथा निर्वाध रूप से बहती रहे, इस हेतु समुचित संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-29 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-1,17,000 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 52,500 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके तथा इसी के अनुरूप वृक्षारोपण योजना में प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। इसी प्रकार समिति ने सुझाव दिया कि भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थयीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. खदान के एक भाग से नदी की धारा निकल रही है, अतः खदान के जिस भाग में नदी की धारा है वहाँ पर खनन नहीं किया जाये तथा पुनरीक्षित उत्पादन योजना ईआईए के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. प्रस्तावित खदान के दूसरी ओर एक अन्य खदान (प्रकरण क्रमांक 9750/23) आवंटित की गई है जिसमें से नदी की धारा बह रही है । नदी की धारा अवरुद्ध न हो तथा निर्वाध रूप से बहती रहे, इस हेतु समुचित संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
5. भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थयीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये ।
7. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
10. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
13. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

14. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
15. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।
16. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
17. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।
18. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

**13. Case No 9749/2023 Shri Raghvendra Singh, R/o C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, District-Jaipur (RJ)-302021, Prior Environment Clearance for Bharaulikhurd River Sand Mine in an area of 10.570 ha. (41400 Cum per annum) (Khasra No. 3349, 3350, 3355, 3402, 3403, 3405), Village-Bharaulikhurd, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP)**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3349, 3350, 3355, 3402, 3403, 3405), Village-Bharaulikhurd, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP) 10.570 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इन्वायरो इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरुग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6469 दिनांक 04/11/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है एवं इनका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

यह रेत सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान दो भागों में आवंटित है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान शासन द्वारा इसी प्रकार स्वीकृत की गई है, जिसमें से ऊपर वाले भाग में पानी होने के कारण खनन प्रस्तावित नहीं है तथा नीचे वाले भाग में खनन किया जायेगा जो अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार है। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-30 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-63,438 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 41,400 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन योजना में दिये गये अक्षांश-देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया। चूँकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके तथा इसी के अनुरूप वृक्षारोपण योजना में प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। इसी प्रकार समिति ने सुझाव दिया कि भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थिरीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये ।
4. भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थयीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
5. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड मार्किंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
8. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।
14. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

15. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

**14. Case No 9750/2023 Shri Raghvendra Singh, R/o C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, District-Jaipur (RJ)-302021 Prior Environment Clearance for Dubka River Sand Mine in an area of 13.510 ha. (75060 Cum per annum) (Khasra No. 1, 208), Village-Dubka, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP)**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1, 208), Village-Dubka, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP) 13.510 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इन्वायरो इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरुग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6531 दिनांक 13/11/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है किंतु खदान का क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल इमेज अनुसार अनुसंधान खदान के अधिकांश भाग में पानी भरा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वह रेत निकलने के कारण ऐसा दिख रहा है तथा तथा पूर्व की गूगल इमेज देखने पर यह स्पष्ट होता है कि आवंटित खनन क्षेत्र में रेत उपलब्ध है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस वर्ष वर्षा अच्छी होने के कारण पर्याप्त मात्रा में रेत उपलब्ध है फिर भी खदान का वह भाग जिसमें पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि इसी खदान के दूसरी ओर एक अन्य खदान (प्रकरण क्रमांक 9748/23) आवंटित की गई है जिसमें से नदी की धारा बह रही है । नदी की धारा अवरुद्ध न हो तथा निर्बाध रूप से बहती रहे, इस हेतु समुचित संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये । प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-103 के सरल क्रमांक-32 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल (60 प्रतिशत)-1,72,650 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 75,060 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल (60 प्रतिशत) से कम है । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके तथा इसी के अनुरूप वृक्षारोपण योजना में प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। इसी प्रकार समिति ने सुझाव दिया कि भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थरीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. प्रस्तावित खदान के दूसरी ओर एक अन्य खदान (प्रकरण क्रमांक 9748/23) आवंटित की गई है जिसमें से नदी की धारा बह रही है। नदी की धारा अवरुद्ध न हो तथा निर्बाध रूप से बहती रहे, इस हेतु समुचित संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
5. भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थरीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाईन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
9. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
12. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
14. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।
15. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
16. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।
17. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

**15. Case No 9751/2023 Shri Raghvendra Singh, R/o C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, District-Jaipur (RJ)-302021, Prior Environment Clearance for Chandawali River Sand Mine in an area of 5.975 ha. (35850 Cum per annum) (Khasra No. 1, 10, 15), Village-Chandawali, Tehsil-Lahar, District-Bhind (MP)**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1, 10, 15), Village-Chandawali, Tehsil-Lahar,

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

District-Bhind (MP) 5.975 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इवायरो इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरुग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6475 दिनांक 07/11/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है किंतु खदान का क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के अधिकांश भाग में नदी का प्रवाह है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-103 के सरल क्रमांक-31 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-36,095 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 34,560 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके तथा इसी के अनुरूप वृक्षारोपण योजना में प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। इसी प्रकार समिति ने सुझाव दिया कि भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थयीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफलेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये ।
4. भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थरीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
5. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
8. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

14. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
15. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

**16. Case No 9752/2023 Shri Raghvendra Singh, R/o C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, District-Jaipur (RJ)-302021, Prior Environment Clearance for Kheriyasindh River Sand Mine in an area of 4.00 ha. (34560 Cum per annum) (Khasra No. 1331), Village-Kheriyasindh, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP)**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1331), Village-Kheriyasindh, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5549 दिनांक 12/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है एवं जिनका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।

यह रेत सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के एक से नदी का प्रवाह है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग से नदी का प्रवाह है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है । परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-25 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल (60 प्रतिशत)-46,560 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 34,560 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल (60 प्रतिशत) से कम है । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके तथा इसी के अनुरूप वृक्षारोपण योजना में प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। इसी प्रकार समिति ने सुझाव दिया कि भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थरीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
4. भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थरीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
8. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।
11. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
12. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
13. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये।
14. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
15. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।

**17. Case No 9755/2023 Shri Raghvendra Singh, R/o C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, District-Jaipur (RJ)-302021, Prior Environment Clearance for Ajnar-1 River Sand Mining Project in an area of 23.810 ha. (119800 Cum per annum) (Khasra No. 1576), Village-Ajnar, Tehsil-Lahar, District-Bhind (MP)**

This is case of Sand Mining. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1576), Village-Ajnar, Tehsil-Lahar, District-Bhind (MP) 23.810 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इन्वायरो

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरुग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5543 दिनांक 12/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है एवं इनका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के एक से नदी का प्रवाह है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग से नदी का प्रवाह है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-14 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल (60 प्रतिशत)-1,82,860 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 1,19,800 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल (60 प्रतिशत) से कम है। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके तथा इसी के अनुरूप वृक्षारोपण योजना में प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। इसी प्रकार समिति ने सुझाव दिया कि भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थयीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

2. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्ड्री कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये ।
4. भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थरीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
5. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
8. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

14. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
15. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।
16. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेगा । परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

**18. Case No 9754/2023 Shri Raghvendra Singh, R/o C-28, Urmila Marg, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, District-Jaipur (RJ)-302021, Prior Environment Clearance for Bachhrauli River Sand Mining Project in an area of 2.97 ha. (16920 Cum per annum) (Khasra No. 545), Village-Bachhrauli, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP)**

This is case of Sand Mining. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 545), Village-Bachhrauli, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP) 2.97 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिव बंसल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इन्वायरो इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरुग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6480 दिनांक 11/11/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने के कारण यह प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया द्वारा अनुमोदित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है जिसके पेज नं.- 102 के सरल क्रमांक-28 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-36,000 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 16,920 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत) से कम है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तरीय भाग से किया जायेगा । ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नदी के पश्चिम भाग में स्वीकृत है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही खनन प्रस्तावित हैं

। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिमी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है । समिति की यह

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 16,920 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 06.73 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.83 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 02.97 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे।
6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 02 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2970 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा :-

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान                 | पौधों की प्रजातियाँ                                                                                                   | मात्रा<br>(संख्या में) |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | नदी के किनारे पर पंक्तियों 6 से 1 नदी तट से )<br>( मे | पंक्ति 3-1- खस, नीम एवं स्थानीय घास पंक्ति 5-4<br>बांस 6- पंक्ति - करंज, जामुन, लसोडा, देनचा, एवं अन्य<br>फलदार वृक्ष | 2000                   |

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

|     |                                                                     |                                                                        |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 2   | परिवहन मार्ग                                                        | खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक                                     | 200  |
| 3   | आवंटित क्षेत्र के आसपास के ग्राम में तथा ग्रामवासियों के वितरण हेतु | आम बेर अमल सीताफल नींबू बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार पौधों की प्रजातियाँ | 770  |
| कुल |                                                                     |                                                                        | 2970 |

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.55 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून, 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

| सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि                                           | राशि (रु. में) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| शासकीय प्राथमिक शाला बछरौली में 20 बेंच व 5 कुर्सियों की व्यवस्था           | 25,000         |
| ग्राम बछरौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण | 30,000         |

### **19. Case No 9756/2023 Shri Shishir Khandar, Owner, R/o Samashis Bhawan, Malik Complex, Tenament Hotel, Nagpur, (MH)-480001, Prior Environment Clearance for Bichua Baggu Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 263), Village-Bichua Baggu, Tehsil-Sausar, District-Chhindwara (MP)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 263), Village-Bichua Baggu, Tehsil-Sausar, District-Chhindwara (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री शिशिर खण्डार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 110 दिनांक 24/01/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, जिनका क्षेत्रफल 5.00 हे. से कम होने के कारण यह प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान शोभना नदी के पास स्थित निजी भूमि पर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 109 दिनांक 24/01/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला छिंदवाड़ा अंतर्गत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की गई है, जिसमें उक्त रेत खनन अनुज्ञा को क्रमांक-59 पर दर्ज कर लिया गया है चूंकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन योजना में दिये गये अक्षांश-देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के बीच से नदी की धारा बह रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह उनकी निजी भूमि है तथा नदी के रास्ता बदल लिये जाने के कारण नदी कृषि भूमि से बह रही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के जिस भाग से नदी बह रही है, वहाँ पर खनन् नहीं किया जायेगा तथा पूर्वी क्षेत्र में स्थित भाग से खनन् किया जायेगा, जिस कारण आवंटित खनन् क्षेत्र का 50 प्रतिशत भाग (0.50 हे.) ही खनन् योग्य है। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि खनन् योग्य क्षेत्र में जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, वह झाड़िया है जिनके फोटोग्राफ प्रस्तुतीकरण में दिया गया है । आवंटित खनन् क्षेत्र के बाहर की ओर पूर्वी दिशा में जो पेड़ लगे हैं, उन्हें काटा नहीं जायेगा तथा बांस का वृक्षारोपण किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जायेगा तथा स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है । समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 10,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.70 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 06.00 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:—
6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 02 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा :—

| क्र. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियाँ                          | मात्रा (संख्या में) |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1    | आसपास के किसानों को वितरण             | आम, जामुन, सीताफल एवं अन्य फलदार प्रजातियाँ  | 600                 |
| 2    | गाँव में वितरण                        | आम, कटहल, सीताफल, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँ | 200                 |
| 3    | नॉन माईनिंग जोन                       | बांस का वृक्षारोपण                           | 400                 |
| कुल  |                                       |                                              | 1200                |

8. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून, 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :—

| सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि               | राशि (रु. में) |
|-------------------------------------------------|----------------|
| बिछुआ बग्गु प्राथमिक शाला में टॉयलेट निर्माण 02 | 50,000         |

**20. Case No 9685/2023 Shri Litesh Jha, Authorized Person, M/s Sainik Industries Private Limited, R/o 201-202 Vikash Plaza, Building No. 2, Local Shopping Center, Kalkaji, New Delhi-110002, Prior Environment Clearance for Shikarganj Sand Deposit Quarry in an area of 2.350 ha. (21000 Cum per annum) (Khasra No. 995, 1003 & 1008), village-Shikarganj, Tehsil –Rampur Naikin, District-Sidhi (MP)**

This is case of Sand Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 995, 1003 & 1008), village-Shikarganj, Tehsil –Rampur Naikin, District-Sidhi (MP) 2.350 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री लितेश झा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 947

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

दिनांक 22/06/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने के कारण यह प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि यह निजी भूमि पर आवंटित एक खोदू-भरू रेत खदान है तथा ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान के लगभग 80 प्रतिशत भाग में वृक्ष/झाड़ियां लगी हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में यह प्रकरण क्रमांक 8845/21 सेक की 535वीं बैठक दिनांक 16/12/21 में प्रस्तुत हुआ था जिसमें समिति द्वारा वृक्षों की इन्वेन्ट्री, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र को नॉन माईनिंग जोन तथा पास में वह रहे नाले से 50 मीटर का सेट बैक छोड़ते हुए रिवाइज सरफेस में पचाया गया था जो उनके द्वारा 30/12/21 को ऑन लाईन अपलोड किया गया था। सेक द्वारा दी गई प्रश्नों का प्रस्तुतीकरण सेक की 542वीं बैठक दिनांक 21/01/22 को किया गया जिसमें सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की अनुशंसा की गई थी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज न होने के कारण सिया ने पत्र क्रमांक 3178 दिनांक 26/02/22 के द्वारा यह निर्णय सूचित किया कि प्रस्तावित खदान की जानकारी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित हो जाने के उपरांत परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन करे। प्रस्तावक ने बताया कि सिया द्वारा अनुमोदित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण पेज नं.- 09 के टेबिल-04 के सरल क्रमांक-01 पर दर्ज है जिसमें अधिकतम उत्पादन क्षमता-35,250 घनमीटर दर्ज है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति 21,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गई है जो अधिकतम उत्पादन क्षमता से कम है। समिति ने पाया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के अक्षांश-देशांस दर्ज नहीं हैं अतः अनुमोदित खनन योजना में दिये गये अक्षांश-देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के दक्षिण भाग से किया जायेगा। समिति ने निर्णय लिया कि सेक की पूर्व 542वीं बैठक दिनांक 21/01/22 को की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाये।

**21. Case No 9733/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Naagjhiri Sand Mine in an area of 10.00 ha. (2000 Cum per annum) (Khasra No. 45/1/1/k, 45/2/k), Village-Naagjhiri, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 45/1/1/k, 45/2/k), Village-Naagjhiri, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 10.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वाटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 381 दिनांक 08/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है किंतु इसका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह खोदू-भरू रेत खदान नर्मदा नदी के पास शासकीय भूमि पर लगभग 50 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान दो भागों में आवंटित की गई है (एक भाग 6.0 हे. तथा दूसरा भाग 4.0 हे.) जिसमें पहला भाग नर्मदा नदी से लगभग 50 मीटर दूर तथा दूसरा भाग नर्मदा नदी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऑन लाईन एक ही भाग की गूगल इमेज जो नदी से 200 मीटर दूर है दिख रही है जबकि वह भाग जो नदी से 50 मीटर दूर है नहीं दिख रही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा दोनों भागों की गूगल इमेज अपलोड की गई थी किंतु प्रस्तुतीकरण में एक ही दिख रही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुतीकरण में दोनों इमेज दिखाई गई है जिसमें खदान का वह भाग जो नदी से 50 मीटर की दूरी पर है (4.0 हे.) उसमें खनन प्रस्तावित नहीं किया है तथा वह भाग (6.0 हे.) जो 200 मीटर दूर है के भी कुछ ही भाग में खनन प्रस्तावित किया गया है क्योंकि मात्रा मात्र 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष है। अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव औचित्य के साथ प्रस्तुत किया जाये तथा प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से दूरी ज्ञात कर उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-125 के सरल क्रमांक-07 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल (60 प्रतिशत)-2,000 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 2,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल (60 प्रतिशत) के बराबर है। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला, धार के पत्र क्रमांक 628 दिनांक 10/03/23 के माध्यम से जिला खनिज अधिकारी ने यह जानकारी सदस्य सचिव, सिया, भोपाल (प्रतिलिपि - सदस्य सचिव, सेक) को प्रेषित की है कि धार जिले की 40 रेत खदानों की सूची में अंक्षांश-देशांश की जानकारी अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में नहीं थी जो इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके तथा इसी के अनुरूप वृक्षारोपण योजना में प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. खदान का वह भाग जो नदी से 50 मीटर की दूरी पर है (4.0 हे.) उसमें खनन प्रस्तावित नहीं किया है तथा वह भाग (6.0 हे.) जो 200 मीटर दूर है के भी कुछ ही भाग में खनन प्रस्तावित

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

किया गया है अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव औचित्य के साथ प्रस्तुत किया जाये।

3. यह खोदू-भरू रेत खदान नर्मदा नदी के पास शासकीय भूमि पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है, अतः प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से दूरी ज्ञात कर उसकी संरक्षण योजना के साथ विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
4. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्ड्री कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
9. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
10. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
11. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।
12. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
13. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
14. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

15. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
16. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

**22. Case No 9734/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Bhavariya Sand Mine in an area of 9.00 ha. (850 Cum per annum) (Khasra No. 284, 309, 322), Village-Bhavariya, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP)**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 284, 309, 322), Village-Bhavariya, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) 9.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वाटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 375 दिनांक 08/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है किंतु इसका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।

यह खोदू-भरू रेत खदान उरी बागनी नदी के पास शासकीय भूमि पर लगभग 150 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में स्थित है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान दो भागों में आवंटित की गई है (एक भाग 6.0 हे. तथा दूसरा भाग 3.0 हे.) । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऑन लाईन एक ही भाग की गूगल इमेज जो नदी से 175 मीटर दूर है दिख रही है जबकि दूसरे भाग की इमेज नहीं दिख रही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा दोनों भागों की गूगल इमेज अपलोड की गई थी किंतु प्रस्तुतीकरण में एक ही दिख रही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुतीकरण में दोनों इमेज दिखाई गई है जिसमें खदान का वह भाग जो नदी से 175 मीटर की दूरी पर है (6.0 हे ) उसमें खनन कुछ ही भाग में खनन प्रस्तावित किया गया है क्योंकि मात्रा मात्र 850 घनमीटर प्रतिवर्ष है तथा दूसरा भाग जो नदी के समीप है में खनन प्रस्तावित नहीं है । अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव औचित्य के साथ प्रस्तुत किया जाये । परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-127 के सरल क्रमांक-28 पर माईनेवल मिनरल पोटेंशियल (60 प्रतिशत)-850 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर भी

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

850 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) के बराबर है । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला, धार के पत्र क्रमांक 628 दिनांक 10/03/23 के माध्यम से जिला खनिज अधिकारी ने यह जानकारी सदस्य सचिव, सिया, भोपाल (प्रतिलिपि – सदस्य सचिव, सेक) को प्रेषित की है कि धार जिले की 40 रेत खदानों की सूची में अंक्षांश-देशांश की जानकारी अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में नहीं थी जो इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके तथा इसी के अनुरूप वृक्षारोपण योजना में प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऑन लाईन एक ही भाग की गूगल इमेज जो नदी से 175 मीटर दूर है दिख रही है जबकि दूसरे भाग की इमेज नहीं दिख रही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा दोनों भागों की गूगल इमेज अपलोड की गई थी किंतु प्रस्तुतीकरण में एक ही दिख रही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुतीकरण में दोनों इमेज दिखाई गई है जिसमें खदान का वह भाग जो नदी से 175 मीटर की दूरी पर है (6.0 हे ) उसमें खनन कुछ ही भाग में खनन प्रस्तावित किया गया है क्योंकि मात्रा मात्र 850 घनमीटर प्रतिवर्ष है तथा दूसरा भाग जो नदी के समीप है में खनन प्रस्तावित नहीं है। अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव औचित्य के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
3. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये ।
5. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाईन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

- हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
  8. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
  9. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
  10. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
  11. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
  12. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
  13. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।
  14. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
  15. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

**23. Case No 9735/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Bhavgaon Sand Mine in an area of 7.00 ha. (2000 Cum per annum) (Khasra No. 114/1), Village-Bhavgaon, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 114/1), Village-Bhavgaon, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 7.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकाजुर्न राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वाटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 377 दिनांक 08/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है किंतु इसका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह खोदू-भरू रेत खदान नर्मदा नदी के पास शासकीय भूमि पर लगभग 100 मीटर की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है, अतः प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से दूरी ज्ञात कर उसकी संरक्षण योजना के साथ विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-125 के सरल क्रमांक-02 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-2,000 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 2,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) के बराबर है। प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला, धार के पत्र क्रमांक 628 दिनांक 10/03/23 के माध्यम से जिला खनिज अधिकारी ने यह जानकारी सदस्य सचिव, सिया, भोपाल (प्रतिलिपि – सदस्य सचिव, सेक) को प्रेषित की है कि धार जिले की 40 रेत खदानों की सूची में अंक्षांश-देशांश की जानकारी अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में नहीं थी जो इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके तथा इसी के अनुरूप वृक्षारोपण योजना में प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. यह खोदू-भरू रेत खदान नर्मदा नदी के पास शासकीय भूमि पर लगभग 100 मीटर की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है, अतः प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से दूरी ज्ञात कर उसकी संरक्षण योजना के साथ विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
4. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाईन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
7. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।
13. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
14. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

**24. Case No 9736/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Imlipura Sand Mine in an area of 6.506 ha. (2300 Cum per annum) (Khasra No. 1, 59, 60, 77), Village- Imlipura, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)**

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1, 59, 60, 77), Village- Imlipura, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 6.506 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 13/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स किएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 369 दिनांक 08/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है किंतु इसका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत खदान कारम नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के कुछ भाग में नदी का पानी भरा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग से नदी का पानी है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार आवंटित खनन क्षेत्र के बीच में एक जल रोकने की संरचना बनी हुई है अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-126 के सरल क्रमांक-18 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-2550 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 2300 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप हैं उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके तथा इसी के अनुरूप वृक्षारोपण योजना में प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है:-

1. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

2. आवंटित खनन् क्षेत्र के बीच में एक जल रोकने की संरचना बनी हुई है अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये ।
5. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाईन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
8. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान

**628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 13 मार्च 2023**

में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

14. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
15. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

(चंद्र मोहन ठाकुर)  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

### **Annexure- 'B'**

#### **Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - j. Minable Potential of sand mine.
  - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

### **Annexure- 'C'**

#### **Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\***

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - p. Minable Potential of sand mine.
  - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

### **Annexure- 'D'**

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

- an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
  17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
  18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
  19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
  20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
  21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
  22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
  23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
  24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
  25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
  26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
  27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
  28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
  29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
  30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
  31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
  32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
  33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
  - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

**खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-**

- |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>नोट 1 :-</b> | स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।                                                                                                                            |
| <b>नोट 2 :-</b> | विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।                                                                                                                                                        |
| <b>नोट 3 :-</b> | पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्टिचिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए । |
| <b>नोट 4 :-</b> | पौधों की ऊँचाई/गोलाई -                                                                                                                                                                                                                          |

## 628वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च 2023

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

| क्र. | स्थल                                                                       | ऊँचाई न्यूनतम   | गोलाई न्यूनतम |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.   | बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र                                             | 02.5 – 03.0 फिट | 03–05 से. मी. |
| 2.   | रोड साईड/स्कूल/ऑगनवाडी                                                     | 03.5 – 05.5 फिट | 05–10 से.मी.  |
| 3.   | पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)<br>तीन वर्षों तक । |                 |               |
| 4.   | आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद                           |                 |               |

**नोट 7 :-** बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।